Test Cloud

# Daily करेंट अफेयर्स

21 अगस्त 2025

## NATIONAL AFFAIRS

### 1. प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपये की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

17 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹11,000 करोड़ है। उद्घाटन समारोह रोहिणी में हुआ, जो राष्ट्रीय राजधानी में भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के बुनियादी ढाँचा विकास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

**• उद्घाटन की गई दो परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) शामिल हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड 10.1 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण पर अनुमानित लागत ₹5,360 करोड़ है।**

**• इसमें दो खंड शामिल हैं: शिव मूर्ति से द्वारका सेक्टर-21 रोड अंडर ब्रिज (RUB) तक 5.9 किलोमीटर का खंड, और दिल्ली-हरियाणा सीमा तक फैला 4.2 किलोमीटर का खंड, जो यूईआर-II को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा का समय काफी कम होने और प्रमुख मार्गों पर यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है।**

**• UER-II परियोजना में अलीपुर को दिचाओं कलां से जोड़ने वाले 22.5 किलोमीटर लंबे गलियारे का विकास शामिल है, जिसमें बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए विकसित संपर्क मार्ग भी शामिल हैं। ₹5,580 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित, UER-II का उद्देश्य दिल्ली के आंतरिक और बाहरी रिंग रोड पर, विशेष रूप से मुकरबा चौक, धौला कुआँ और मधुबन चौक जैसे भीड़भाड़ वाले जंक्शनों पर यातायात के दबाव को कम करना है। इस परियोजना से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी बढ़ने और एनसीआर में औद्योगिक केंद्रों तक पहुँच में सुधार होने की उम्मीद है।**

**Key Points:-**

(i) उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित थे। कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं में शामिल निर्माण श्रमिकों से बातचीत की और इन बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यों के सफल समापन में उनके योगदान की सराहना की। यह कार्यक्रम जन्माष्टमी के उत्सव के साथ भी मेल खाता था, जिससे इस अवसर का सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ गया।

(ii) ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने और NCR के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II से यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने, यात्रा समय को कम करने और क्षेत्र में समग्र परिवहन दक्षता में सुधार की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, ये परियोजनाएँ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो मेट्रो लाइनों, एक नए रेलवे स्टेशन और एक बस डिपो को जोड़ती हैं, जिससे एकीकृत शहरी गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा मिलता है।

(iii) इन राजमार्गों का विकास विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को

दर्शाता है जो नागरिकों के जीवन को सुगम बनाता है। कनेक्टिविटी में सुधार और भीड़भाड़ को कम करके, इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास और सतत विकास में योगदान देना है। द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-II का सफल समापन और उद्घाटन एक आधुनिक और अच्छी तरह से जुड़ी राष्ट्रीय राजधानी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## 2. IIT मद्रास ने भारत के पहले सिलिकॉन फोटोनिक्स-आधारित हाई-स्पीड QRNG के लिए इंद्रारका क्वांटम टेक्नोलॉजीज के साथ 1 करोड़ रुपये के लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT-M) के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय (TTO) ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन (Si) फोटोनिक्स-आधारित हाई-स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (QRNG ) तकनीक को वाणिज्यिक तैनाती के लिए स्थानांतरित करने के लिए इंद्रार्क क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1 करोड़ रुपये के लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

**• यह लाइसेंसिंग समझौता भारत के क्वांटम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह इंद्रार्क क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को QRNG तकनीक का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसे IIT-M के प्रोग्रामेबल फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम्स (CPPICS) केंद्र में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। इस सहयोग का उद्देश्य भारत में अत्याधुनिक क्वांटम समाधानों को अपनाने में तेज़ी लाना है।**

**• इस परियोजना का नेतृत्व IIT-M के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर बिजॉय कृष्णा डी ने किया, जो CPPICS में मुख्य अन्वेषक के रूप में भी कार्यरत हैं।**

**• टीम ने सिलिकॉन फोटोनिक्स-आधारित QRNG मॉड्यूल को सफलतापूर्वक डिजाइन और परीक्षण किया, जिससे क्वांटम यादृच्छिक संख्याओं का उच्च गति और सुरक्षित उत्पादन सुनिश्चित हुआ, जो उन्नत क्रिप्टोग्राफिक और कम्प्यूटेशनल अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।**

**Key Points:-**

(i) QRNG मॉड्यूल के पिछले प्रोटोटाइप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला-क्वांटम टेक्नोलॉजीज (DYSL-QT) को सौंपे गए थे। बाद में, व्यावहारिक क्वांटम सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए, चेन्नई, तमिलनाडु स्थित सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स एंड सिक्योरिटी (SETS) में उन्नत संस्करण तैनात किए गए, जिससे वास्तविक दुनिया में तैनाती के लिए इसकी तैयारी का प्रदर्शन हुआ।

(ii) QRNG तकनीक के रक्षा, वित्तीय लेनदेन, वैज्ञानिक सिमुलेशन और क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिदम जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग हैं। सिलिकॉन फोटोनिक्स का लाभ उठाकर, यह तकनीक मापनीय, उच्च गति और सुरक्षित यादृच्छिक संख्या सृजन सुनिश्चित करती है, जिससे भारत वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता है।

(iii) यह लाइसेंसिंग IIT-M और भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अत्याधुनिक क्यूआरएनजी तकनीक को व्यावसायिक उपयोग के लिए हस्तांतरित करके, यह सहयोग अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग के बीच की कड़ी को मज़बूत करता है, और क्वांटम-सक्षम प्रौद्योगिकियों में नवाचार, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

## 3. कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में 1,507 करोड़ रुपये के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी।

19 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंज़ूरी दे दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) आधुनिक बुनियादी ढाँचे और मज़बूत क्षेत्रीय संपर्क के साथ सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालने के लिए इस नए हवाई अड्डे का विकास करेगा।

**• प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने ₹1,507 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। CCEA की मंज़ूरी दक्षिणी राजस्थान में हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतीक है, जो अपने तेज़ी से बढ़ते शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है।**

**• राजस्थान सरकार ने AAI को 440.06 हेक्टेयर (लगभग 1,089 एकड़) भूमि निःशुल्क आवंटित की है। इस भूमि आवंटन से एक पूर्ण-सेवा हवाई अड्डे का विकास संभव होगा जो एयरबस A-321 श्रेणी के विमानों को सहारा दे सकेगा और प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों (MPPA) तक का प्रबंधन कर सकेगा।**

**• हवाई अड्डे में 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन, 3,200 मीटर का रनवे, एप्रन स्पेस, टैक्सीवे और अन्य आवश्यक सुविधाएँ होंगी। टर्मिनल को व्यस्त समय में 1,000 यात्रियों (PHP) को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह वाणिज्यिक विमानों के संचालन को सक्षम करेगा।**

**Key Points:-**

(i) केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) अपने आंतरिक संसाधनों से इस परियोजना का वित्तपोषण करेगा। वैष्णव ने ज़ोर देकर कहा कि नया हवाई अड्डा क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देगा और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।

(ii) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मंज़ूरी की सराहना करते हुए बताया कि यह परियोजना हाड़ौती क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोज़गार को बढ़ावा देगी। उन्होंने भूमि हस्तांतरण में पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार के योगदान की सराहना की।

(iii) हवाई संपर्क में सुधार के अलावा, नए हवाई अड्डे से लाखों छात्रों और आगंतुकों के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करके कोटा की शैक्षिक केंद्र के रूप में छवि बदलने की उम्मीद है। यह औद्योगिक रसद को भी बढ़ावा देगा और आस-पास के विरासत और प्राकृतिक स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देगा।

### 4. पश्चिम बंगाल ने वापस लौटने वाले बंगाली प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 'श्रमश्री' योजना शुरू की।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लौटने वाले बंगाली प्रवासी श्रमिकों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 'श्रमश्री' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बाहर नौकरी छूटने से प्रभावित श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

- **श्रमश्री योजना उन प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो भारत के अन्य राज्यों में कार्यरत थे, लेकिन आर्थिक चुनौतियों, छंटनी या सामाजिक कारणों से पश्चिम बंगाल लौटने को मजबूर हुए। यह योजना श्रमिकों को फिर से स्थापित करने में मदद करने के लिए कौशल विकास और तत्काल वित्तीय सहायता दोनों सुनिश्चित करेगी।**

- **यह पहल पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के अंतर्गत लागू की जाएगी, जिसकी राज्य सरकार सक्रिय निगरानी करेगी। लौटने वाले श्रमिकों को एक विशेष राज्य पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTs) प्राप्त होगा।**

**Key Points:-**

(i) प्रत्येक पात्र श्रमिक को एकमुश्त वित्तीय अनुदान के साथ-साथ राज्य कल्याणकारी योजनाओं, आवास सहायता और स्थानीय उद्योगों, MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) तथा कृषि में रोजगार संबंध उपलब्ध कराए जाएँगे। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एकीकृत करने की भी योजना बना रहा है।

(ii) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि यह योजना न केवल राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य से बाहर पलायन करने वाले श्रमिकों की भेद्यता को भी कम करेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रवासन चुनौतियों को स्थानीय विकास के अवसरों में बदलना है।

(iii) इस योजना से लाखों प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों से, जो पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल के उच्च प्रवास वाले क्षेत्र रहे हैं।

## INTERNATIONAL

### 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त घोषित किया।

अगस्त 2025 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र (SEAR) कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर नेपाल को रूबेला को एक जन

स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए मान्यता दी। यह उपलब्धि नेपाल को इस संक्रामक वायरल रोग पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने वाले क्षेत्र के अग्रणी देशों में शामिल करती है।

**• रूबेला, जिसे जर्मन मीज़ल्स भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर हल्का बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते पैदा करता है। हालाँकि इसे अक्सर बच्चों और वयस्कों में एक हल्की बीमारी माना जाता है, फिर भी इसकी संभावित जटिलताओं के कारण इसकी रोकथाम एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य बनी हुई है।**

**• रूबेला गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से गर्भपात, मृत जन्म, या नवजात शिशुओं में गंभीर जन्मजात दोष हो सकते हैं। इसलिए देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए टीकाकरण और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है।**

**• रूबेला के सबसे गंभीर परिणामों में से एक जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (CRS) है, जो शिशुओं में कई तरह के जन्मजात दोष पैदा कर सकता है। CRS से श्रवण दोष, हृदय संबंधी दोष, मोतियाबिंद और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं, जिससे निरंतर टीकाकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाता है।**

**Key Points:-**

(i) नेपाल की उपलब्धि रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से संभव हुई, जिसमें बच्चों के बीच 95% से अधिक टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना, कई राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाना और रोग की घटनाओं की निगरानी के लिए मजबूत प्रयोगशाला-आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करना शामिल है।

(ii) इस मान्यता के साथ, नेपाल WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला को खत्म करने वाला छठा देश बन गया है, जो भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक (DPR) कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर-लेस्ते के साथ शामिल हो गया है।

(iii) यह उपलब्धि नेपाल के प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों और जनसंख्या स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

## 2. दुबई ने बिजनेस लाइसेंसिंग को सरल बनाने और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'वन फ्रीज़ोन पासपोर्ट' लॉन्च किया।

22 जुलाई, 2025 को, दुबई ने वन फ़्रीज़ोन पासपोर्ट की शुरुआत की, जो एक नई प्रणाली है जो कंपनियों को सिर्फ़ एक लाइसेंस के साथ कई फ़्रीज़ोन में काम करने की अनुमति देती है। इस कदम से व्यापार का विस्तार तेज़ होगा, कागजी कार्रवाई कम होगी और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होगा।

**• पहले, दुबई में व्यवसायों को प्रत्येक मुक्त क्षेत्र के लिए अलग-अलग व्यापार लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब, वन फ्रीज़ोन पासपोर्ट के साथ, वे लंबी पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रिया को दोहराए बिना अन्य सहभागी मुक्त क्षेत्रों में विस्तार कर सकते हैं।**

**• यह परियोजना दुबई के प्रथम उप-शासक और दुबई मुक्त क्षेत्र परिषद (DFZC) के अध्यक्ष शेख मकतूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह दुबई के व्यावसायिक**

**नियमों को आसान बनाने पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।**

**• एक बड़ी उपलब्धि तब हुई जब वैश्विक फ़ैशन ब्रांड, लुई वुइटन, इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी बन गई। सिर्फ़ पाँच दिनों में, इसने जेबेल अली फ़्री ज़ोन (JAFZA) स्थित अपने गोदाम से दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फ़्री ज़ोन (DWTC फ़्री ज़ोन) में एक लाइसेंस के ज़रिए अपना कार्यालय खोल लिया।**

**Key Points:-**

(i) दुबई फ्री जोन्स काउंसिल ने इस पहल को दुबई आर्थिक एजेंडा डी33 के साथ भी जोड़ा है, जिसका लक्ष्य वैश्विक व्यवसायों को आकर्षित करने और व्यापार में वृद्धि के माध्यम से 2033 तक दुबई के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करना है।

(ii) इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सरकार ने एक डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। तकनीकी एकीकरण की बदौलत कंपनियाँ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, शुल्क का भुगतान कर सकती हैं और पाँच कार्यदिवसों के भीतर मंज़ूरी प्राप्त कर सकती हैं।

(iii) DMCC (दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर), JAFZA, दुबई सिलिकॉन ओएसिस (DSO) और DIFC (दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर) जैसे प्रमुख मुक्त क्षेत्र इस पासपोर्ट कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो लाइसेंसिंग और अनुपालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली बनाते हैं।

## BANKING & FINANCE

### 1. SEBI ने मार्जिन प्लेज-रीप्लेज फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समयसीमा 10 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी है।

अगस्त 2025 में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मार्जिन प्लेज-रीप्लेज ढांचे के कार्यान्वयन की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। अनुपालन की नई तिथि 1 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 10 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है, जिससे बाजार सहभागियों को अनुकूलन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

**• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत एक परिपत्र के माध्यम से यह संशोधित समय सीमा जारी की, जिसे सेबी (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 1992 के अध्याय VII के विनियम 30 के साथ पढ़ा गया। इस विस्तार का उद्देश्य सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, दलालों द्वारा ग्राहक प्रतिभूतियों के दुरुपयोग को कम करना और पारदर्शी लेनदेन निशान बनाए रखना है।**

**• यह ढाँचा मूल रूप से जून 2025 में पेश किया गया था, जिसके अनुसार इक्विटी और डेरिवेटिव खंडों में सभी मार्जिन दायित्वों का भुगतान केवल गिरवी और पुनः गिरवी की डिपॉजिटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि ब्रोकर ग्राहक प्रतिभूतियों का दुरुपयोग न करें और एक सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया प्रदान करें।**

**• इस ढाँचे की एक प्रमुख विशेषता स्वचालित आह्वान है, जिसके तहत एक बार ग्राहक द्वारा मार्जिन-गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का आह्वान हो जाने पर, उन्हें ग्राहक के डीमैट (डीमैटेरियलाइज्ड)**

**खाते में शीघ्र भुगतान के लिए तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। यह स्वचालन देरी के जोखिम को समाप्त करता है और लेनदेन चक्र में एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करता है।**

**Key Points:-**

(i) SEBI ने पे-इन के लिए प्लेज रिलीज़ नामक एक नई सुविधा भी शुरू की है, जिससे गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को तुरंत जारी किया जा सकता है और पे-इन ब्लॉक ग्राहक के डीमैट खाते में स्थापित किया जा सकता है। इससे कई मैन्युअल निर्देशों की आवश्यकता कम हो जाती है और डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से निर्बाध अनुपालन संभव हो जाता है।

(ii) इस कदम से दलालों द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के दुरुपयोग में उल्लेखनीय कमी आने और निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। डिपॉजिटरी को भी इस प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यक्षमता सृजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(iii) एक बार पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने पर, ब्रोकरों को गिरवी वापस लेने और डिलीवरी के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम स्वयं ही लेनदेन दायित्वों को मान्य और स्वचालित रूप से पूरा कर लेगा।

## 2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI कार्ड ने रुपे और वीज़ा पर 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड' लॉन्च किया।

अगस्त 2025 में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सहायक कंपनी, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (SBICPSL) के साथ मिलकर 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड' नाम से एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारत भर के ग्राहकों को बेहतर मूल्य, सुविधा और एक बेहतरीन खरीदारी अनुभव प्रदान करना है।

- **यह नया लॉन्च किया गया क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र और SBICPSL के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के तहत विविध वित्तीय और जीवनशैली संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेश किया गया है। यह कार्ड रुपे और वीज़ा नेटवर्क के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह से स्वीकार्य होगा।**

- **बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड तीन वेरिएंट्स - एलीट, प्राइम और सिम्पलीसेव में उपलब्ध होगा, जो अलग-अलग आय और जीवनशैली वर्ग के ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। प्रत्येक वेरिएंट में विशेष सुविधाएँ, रिवॉर्ड प्रोग्राम और खर्च संबंधी लाभ शामिल हैं।**

- **इस साझेदारी का उद्देश्य कार्डधारकों को त्वरित रिवॉर्ड पॉइंट, अधिभार छूट, यात्रा और भोजन पर छूट, उपयोगिता बिल भुगतान सुविधाएँ और बेहतर खरीदारी ऑफ़र जैसे कई लाभ प्रदान करना है।**

**इससे दैनिक और प्रीमियम खर्च श्रेणियों में मूल्यवर्धन सुनिश्चित होता है।**

**Key Points:-**

(i) इस सह-ब्रांडेड कार्ड को लॉन्च करके, दोनों संस्थान भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने के विस्तार के लिए अपनी वित्तीय विशेषज्ञता और व्यापक ग्राहक आधार का लाभ उठा रहे हैं।

(ii) यह सरकार के कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और रुपे जैसे स्वदेशी भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप भी है।

(iii) यह पहल अभिनव बैंकिंग उत्पादों के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जबकि SBICPSL रणनीतिक बैंकिंग गठजोड़ के साथ भारत में अग्रणी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है।

## SPORTS

### 1. भाविना पटेल ने USA में ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं में शीर्ष पदक जीते, महिला एकल में विश्व नंबर 1 बनीं।

अगस्त 2025 में, भारतीय पैरा टेबल टेनिस स्टार भाविना हसमुखभाई पटेल, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में सहायक निदेशक भी हैं, ने स्पोकेन, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) विश्व पैरा स्पर्धाओं में उल्लेखनीय जीत हासिल की। उनकी उपलब्धियों ने भारतीय पैरा खेलों को वैश्विक पहचान दिलाई।

**• 6 से 8 अगस्त 2025 तक आयोजित ITTF वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में, भाविना पटेल ने महिला एकल वर्ग 4-5 वर्ग में रजत पदक जीता। इस आयोजन में उभरती पैरा टेबल टेनिस प्रतिभाओं को शामिल किया गया और प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया।**

**• इसके बाद उन्होंने स्पोकेन में ही 9 से 13 अगस्त 2025 तक आयोजित ITTF वर्ल्ड पैरा एलीट इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया। दुनिया की कुछ सबसे मज़बूत खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए, भाविना पटेल ने महिला एकल वर्ग 4-5 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे उनकी निरंतरता और दृढ़ संकल्प का परिचय मिलता है।**

**• इन लगातार जीतों की बदौलत भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस के महिला एकल वर्ग 1-5 वर्ग में विश्व में नंबर 1 स्थान पर पहुँच गईं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो वैश्विक पैरा खेलों में भारतीय एथलीटों के बढ़ते कद को दर्शाती है।**

**Key Points:-**

(i) भाविना पटेल भारत की सबसे सफल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक रही हैं, जिन्होंने इससे पहले टोक्यो 2020 पैरालिंपिक में महिला एकल वर्ग 4 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उनकी हालिया सफलताएँ वैश्विक स्तर पर भारतीय पैरा खेलों की अग्रणी के रूप में उनकी विरासत को और मज़बूत करती हैं।

(ii) एक ESIC अधिकारी और एक अंतरराष्ट्रीय एथलीट के रूप में उनकी दोहरी भूमिका, पैरा एथलीटों के प्रति भारतीय संस्थानों द्वारा दिए गए समर्थन को भी दर्शाती है। पटेल की यात्रा भारत की विश्वस्तरीय प्रतिभाओं को निखारने में समावेशिता,

लचीलेपन और सरकार द्वारा समर्थित सहयोग के महत्व पर ज़ोर देती है।

## AWARDS

### 1. मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया।

18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में राजस्थान के श्रीगंगानगर की मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। वह नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

- **मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा से ताज प्राप्त किया। अन्य विजेताओं में तान्या शर्मा (उत्तर प्रदेश) प्रथम रनर-अप, महक ढींगरा (हरियाणा) द्वितीय रनर-अप और अमीशी कौशिक (हरियाणा) तृतीय रनर-अप रहीं।**

- **इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों सहित पूरे भारत से 48 प्रतियोगियों ने भाग लिया।**

**Key Points:-**

(i) फिनाले का निर्णायक मंडल एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया, जिसमें निखिल आनंद (मिस यूनिवर्स इंडिया के मालिक), अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, रिया सिंहा (मिस यूनिवर्स इंडिया 2015) और फिल्म निर्माता फरहाद सामजी के साथ-साथ एक्ट नाउ फाउंडेशन के संस्थापक राजीव के श्रीवास्तव भी शामिल थे।

(ii) ग्लामानन्द ग्रुप द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मनिका की पहल न्यूरोनोवा पर भी प्रकाश डाला गया, जो न्यूरोडाइवर्जेंस और ADHD (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) और डिस्लेक्सिया जैसे विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है।

(iii) नई दिल्ली से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक, 22 वर्षीय मनिका ललित कला अकादमी और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। इस राष्ट्रीय ताज को हासिल करने से पहले, उन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब भी जीता था।

## App and Web Portal

### 1. भारत सरकार ने रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए PM-VBRY पोर्टल लॉन्च किया।

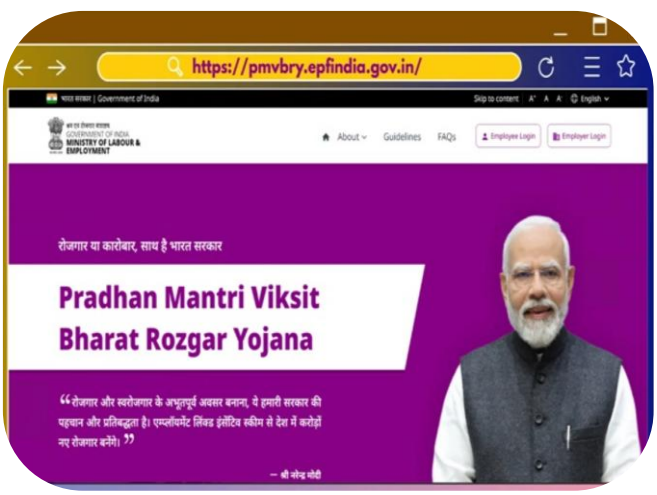


18 अगस्त, 2025 को, भारत सरकार (GoI) ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और कार्यक्रम के तहत वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने

के लिए, एक रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना, समर्पित PM-VBRY पोर्टल लॉन्च किया।

**• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) को मंज़ूरी दी गई थी। रोज़गार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ, इसे औपचारिक रूप से 01 अगस्त, 2025 को लागू किया गया।**

**• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली के लाल किले से अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में PM-VBRY की घोषणा की। उन्होंने रोजगार सृजन, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, और सभी उद्योगों में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में इस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।**

**• एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) के रूप में कार्यान्वित, PM-VBRY का उद्देश्य नए रोज़गार के अवसर पैदा करना, रोज़गार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना है। यह योजना भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान विकास, कौशल विकास और समावेशी रोज़गार पर ज़ोर देती है।**

**Key Points:-**

(i) PM-VBRY का लक्ष्य 01 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों का सृजन करना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ पद पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं, जिसका उद्देश्य कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

(ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoL&E) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से PM-VBRY के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। मंत्रालय इस योजना के तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए पंजीकरण सुनिश्चित करता है, अनुपालन की निगरानी करता है और रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ELI) के वितरण का प्रबंधन करता है।

(iii) PM-VBRY पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in/ या https://pmvbry.labour.gov.in/) नियोक्ताओं के लिए एकमुश्त पंजीकरण और योजना के लाभों तक पहुँच प्रदान करता है। भाग-A पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मासिक सहायता प्रदान करता है, जबकि भाग-B नियोक्ताओं को भविष्य निधि अंशदान में सहायता प्रदान करता है, जिससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

## 2. PRGI ने समाचार पत्र और पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए 'प्रेस सेवा पोर्टल' लॉन्च किया।

अगस्त 2025 में, भारतीय प्रेस महापंजीयक (PRGI), योगेश बावेजा ने प्रेस सेवा पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की। यह एक एकल-खिड़की ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार, अनुमोदन में तेज़ी लाना और पूरे भारत में प्रकाशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना है।

**• प्रेस सेवा पोर्टल प्रकाशकों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे लंबी पंजीकरण प्रक्रिया और प्रशासनिक अड़चनों, को दूर करने के लिए शुरू**

**किया गया था। एकल-खिड़की समाधान प्रदान करके, यह पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में तेज़ अनुमोदन और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अधिक कुशलता से संचालित करने में मदद मिलती है।**

**• यह घोषणा तेलंगाना के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के अधीन, हैदराबाद स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा आयोजित 'वार्तालाप' नामक कार्यशाला में की गई। इस कार्यक्रम में प्रकाशन क्षेत्र के हितधारकों ने पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और अनुपालन को आसान बनाने पर चर्चा की।**

**Key Points:-**

(i) कार्यक्रम के दौरान, PIB हैदराबाद की अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) श्रुति पाटिल ने बताया कि PIB हैदराबाद और PRGI के सहयोग से प्रकाशकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य वास्तविक समय पर सहायता प्रदान करना और पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का कुशलतापूर्वक समाधान करना है।

(ii) PRGI योगेश बावेजा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रेस सेवा पोर्टल, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, यह पोर्टल कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रकाशकों के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार लाएगा।

(iii) प्रेस सेवा पोर्टल का शुभारंभ भारत के प्रकाशन पारिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और डिजिटल सहायता प्रदान करके, यह पोर्टल पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को मज़बूत करता है, जिससे मीडिया और प्रकाशन क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

## IMPORTANT DAYS

### 1. विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त 2025 को मनाया गया।

विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सर रोनाल्ड रॉस द्वारा 1897 में की गई इस अभूतपूर्व खोज के सम्मान में मनाया जाता है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज़ मच्छरों के काटने से फैलता है। यह दिवस मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है जो वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई हैं।

**• 20 अगस्त 1897 को, भारत के सिकंदराबाद में कार्यरत सर रोनाल्ड रॉस ने एक मच्छर की आंत में मलेरिया परजीवी की पहचान की, जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि मच्छर ही मनुष्यों में मलेरिया फैलाते हैं। बाद में उन्होंने इस तिथि को "मच्छर दिवस" घोषित किया - जो विश्व मच्छर दिवस का अग्रदूत था। 1930 के दशक में, जब दुनिया भर के चिकित्सा समुदायों ने रॉस की खोज को अपनाया, तो इस दिवस को औपचारिक वैश्विक मान्यता मिली।**

**• यह दिन डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते बोझ की याद दिलाता है। ये बीमारियाँ स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर, खासकर मानसून प्रभावित क्षेत्रों में, भारी दबाव डालती हैं।**

**• कुछ प्रगति के बावजूद, सार्वभौमिक टीके अभी भी अप्राप्य हैं, जिससे रोकथाम और जागरूकता आवश्यक हो गई है।**

**Key Points:-**

(i) विश्व मच्छर दिवस 2025 का वैश्विक विषय है "अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेज़ी लाना।" यह दुनिया भर में वंचित समुदायों में मलेरिया की रोकथाम, निदान और उपचार तक समान पहुँच सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

(ii) इस दिन, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, सरकारें और समुदाय शिक्षा अभियान, सफाई अभियान और जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं। सुरक्षात्मक उपायों पर ज़ोर दिया जाता है—स्थिर पानी को हटाना, विकर्षक का उपयोग करना, सुरक्षात्मक कपड़े पहनना और खिड़कियों पर जाली लगाना। यह दिन वैज्ञानिक उपलब्धियों को ठोस जन स्वास्थ्य कार्रवाई में बदलने में मदद करता है।

(iii) भारत में, मानसून का मौसम वेक्टर जनित संक्रमणों में वृद्धि को बढ़ावा देता है, खासकर घनी आबादी वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। नियंत्रण प्रयासों के बावजूद, मच्छरों की बड़ी आबादी को बढ़ावा देने वाली गर्म और आर्द्र परिस्थितियों के कारण, प्रकोप अक्सर होते रहते हैं। व्यापक टीकाकरण का अभाव जागरूकता और जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप के महत्व को और भी रेखांकित करता है।

## 2. विश्व मानवतावादी दिवस 2025, 19 अगस्त को मनाया गया।

विश्व मानवतावादी दिवस (WHD) 2025, 19 अगस्त 2025 को विश्व स्तर पर उन मानवीय कार्यकर्ताओं के सम्मान में मनाया गया, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कमजोर समुदायों की मदद करते हुए अपनी जान गंवाई या घायल हुए। यह दिवस इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय पर 2003 में हुए हमले की बरसी का भी प्रतीक है।

**• 2025 का यह दिवस 2003 के बगदाद हमले की 22वीं बरसी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 लोगों की जान चली गई थी। 2025 का विषय है "वैश्विक एकजुटता को मज़बूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना"।**

**• विश्व मानवतावादी दिवस का अभियान 2010 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) द्वारा दुनिया भर में मानवतावादी कार्यकर्ताओं के योगदान और बलिदान को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था।**

**Key Points:-**

(i) 11 दिसंबर 2008 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संकल्प A/RES/63/139 को अपनाया, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित किया गया।

(ii) विश्व मानवतावादी दिवस का पहला आधिकारिक

आयोजन 19 अगस्त 2009 को हुआ, जिसने मानवीय सेवा और बलिदान को सम्मानित करने की वार्षिक वैश्विक परंपरा की स्थापना की।

### 3. विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, 2025 को मनाया गया।

विश्व फोटोग्राफी दिवस, जिसे विश्व फोटो दिवस भी कहा जाता है, हर साल 19 अगस्त को फोटोग्राफी के इतिहास, कला, विज्ञान और प्रभाव का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह प्रारंभिक फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं के आविष्कार का स्मरण भी करता है और दुनिया भर के फोटोग्राफरों को सम्मानित करता है।

- **विश्व फोटोग्राफी दिवस, 1837 में लुई डागुएरे द्वारा विकसित पहली व्यावहारिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया, डागुएरियोटाइप के आविष्कार के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी को संचार के एक सार्वभौमिक माध्यम के रूप में उजागर करता है।**

- **2025 के लिए आधिकारिक थीम "मेरी पसंदीदा फोटो" है, जो दुनिया भर के लोगों को फोटोग्राफी के माध्यम से खींची गई अपनी सबसे प्रिय छवियों और यादों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।**

**Key Points:-**

(i) 'फ़ोटोग्राफ़ी' शब्द, जिसका अर्थ है 'प्रकाश से चित्र बनाना', पहली बार 1839 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जॉन हर्शल द्वारा गढ़ा गया था। उसी वर्ष, फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी द्वारा डग्युरियोटाइप के आविष्कार की आधिकारिक घोषणा की गई थी।

(ii) 2009 में, फोटोग्राफी की कला और विज्ञान के सम्मान में प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने का विचार औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। पहला आधिकारिक वैश्विक दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था।

(iii) 2025 के लिए, 12 से 26 अगस्त 2025 तक दो सप्ताह का विश्व फोटोग्राफी सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के फोटोग्राफरों, संस्थानों और उत्साही लोगों को प्रदर्शनियों, अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

### 4. राजीव गांधी की सद्भावना की विरासत को सम्मान देने के लिए 20 अगस्त को प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है।

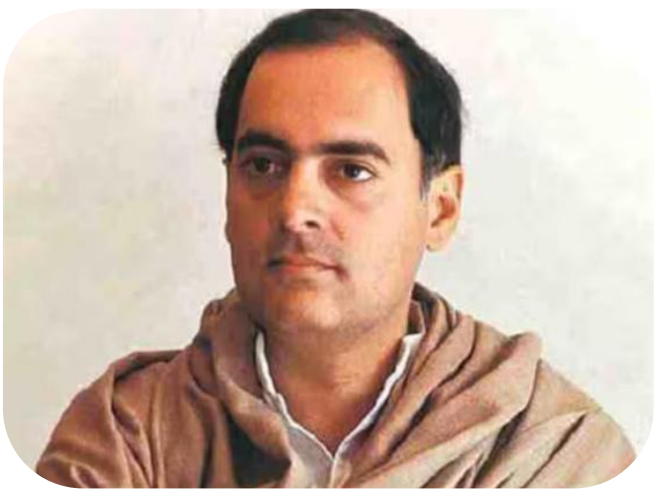

हर साल 20 अगस्त को, भारत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस (जिसे सद्भाव दिवस भी कहा जाता है) मनाता है। यह दिन शांति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के उनके दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, साथ ही नागरिकों से विविध समुदायों में सद्भावना और एकता बनाए रखने का आह्वान करता है।

**• सद्भावना दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 1991 में राजीव गांधी की हत्या के एक साल बाद 20 अगस्त 1992 को मनाया गया था। यह पहल राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने और शांति और समावेशिता के उनके आदर्शों को कायम रखने के लिए शुरू की गई थी।**

**• "सद्भावना" शब्द का अर्थ "सद्भावना" या "सद्भावना" होता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों के बीच सहानुभूति, सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालना है, जिसका उद्देश्य भारत के सामाजिक ताने-बाने को मज़बूत करना है।**

**• भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री (1984-1989) राजीव गांधी अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण, तकनीकी उन्नति पर ज़ोर, शैक्षिक सुधार और शासन के आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। सद्भावना दिवस एकता, व्यवस्थित आधुनिकीकरण और राष्ट्र निर्माण की उनकी चिरस्थायी विरासत को दर्शाता है।**

**Key Points:-**

(i) सद्भावना दिवस पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जिनमें सर्वधर्म प्रार्थनाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, वृक्षारोपण अभियान और सार्वजनिक प्रतिज्ञाएँ शामिल हैं। ये पहल शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में आयोजित की जाती हैं।

(ii) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 1992 में स्थापित, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार के तहत ₹10 लाख की नकद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

## DEFENCE

### 1. भारत ने भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूत करने के लिए 97 तेजस मार्क 1A जेट के लिए 62,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी।

19 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 97 तेजस मार्क 1A हल्के लड़ाकू विमान (LCA) खरीदने के लिए ₹62,000 करोड़ के सौदे को मंज़ूरी दे दी। इस अधिग्रहण से स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकेगा।

**• यह मंजूरी तेजस मार्क 1A जेट के लिए दूसरा बड़ा ऑर्डर है, इससे पहले 2021 में लगभग 48,000 करोड़ रुपये मूल्य के 83 विमानों के लिए सौदा हुआ था। इस नई खरीद के साथ, भारतीय वायुसेना के कुल तेजस मार्क 1ए बेड़े में 180 विमान हो जाएंगे, जिससे घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी।**

**• तेजस मार्क 1A में 65% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री है, और इसमें देश भर के 500 से ज़्यादा छोटे और मध्यम उद्यम शामिल हैं। AESA रडार, उन्नत एवियोनिक्स, EW सिस्टम और उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमताओं से लैस, यह विमान रक्षा तकनीक में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।**

**Key Points:-**

(i) यह अधिग्रहण रणनीतिक रूप से सही समय पर किया गया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 तक अपने पुराने मिग-21 बेड़े को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बना रही है। नया तेजस मार्क 1ए विमान वायु रक्षा और सटीक हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तथा भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा।

(ii) इस घोषणा के बाद, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसे रक्षा-केंद्रित शेयरों में 3.5% तक की तेजी आई, जो निवेशकों के उत्साह को दर्शाता है। प्रमुख निर्माता, HAL, 2025 और 2032 के बीच डिलीवरी की समय-सीमा को पूरा करने के लिए अपने नासिक संयंत्र में उत्पादन बढ़ाएगा।

## Static GK

| | | |
|---|---|---|
| **WHO** | स्थापना: 7 अप्रैल 1948 | मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड |
| **National Highways Authority of India (NHAI)** | अध्यक्ष : संतोष कुमार यादव | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **Airports Authority of India** | अध्यक्ष: विपिन कुमार | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **SEBI** | अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे | मुख्यालय: मुंबई |
| **Indian Air Force (IAF)** | वायु सेना उप प्रमुख (DCAS): एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती | मुख्यालय: नई दिल्ली |
| **West Bengal** | मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी | राज्यपाल: सी. वी. आनंद बोस |